

## राज्यपाल ने कुलपति फोरम का उद्घाटन किया

### शिक्षा एक मिशन है उसे व्यापार नहीं बनाना चाहिए - राज्यपाल

दिनांक: 27 सितम्बर, 2016

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने आज इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में दैनिक जागरण समाचार पत्र द्वारा आयोजित कुलपति फोरम 'उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा: वर्तमान और भविष्य' का उद्घाटन किया। इस अवसर पर दैनिक जागरण के सम्पादक श्री दिलीप अवस्थी, विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य विश्वविद्यालयों, सम विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण तथा महाविद्यालयों के प्राचार्यगण सहित बड़ी संख्या में शिक्षाविद् उपस्थित थे। राज्यपाल ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान उच्च शिक्षा से मेरा संबंध कुलाधिपति के तौर पर दो साल दो माह का है। मैंने अब तक जो देखा वह वर्तमान है और भविष्य में क्या करना है, यह देखने का काम शिक्षाविदों और कुलपतियों का है। हमारा देश ज्ञानयुक्त समाज के रूप में उभर रहा है। ज्ञानवान समाज के निर्माण में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उच्च शिक्षा के विकास में हमें इसी भूमिका पर विचार करना चाहिए। 2020 में भारत विश्व में सबसे अधिक युवा देश होगा। हमारे युवा मानव संसाधन की दृष्टि से हमारी पूंजी हैं, उन्हें उचित दिशा-निर्देशन देकर देश के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर हम युवाओं को उचित दिशा-निर्देश नहीं दे सके तो यही पूंजी हमारे लिए जिम्मेदारी का विकराल रूप धारण कर लेगी।

श्री नाईक ने कहा कि राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) द्वारा 140 विश्वविद्यालयों में किये गये मूल्यांकन में 32 प्रतिशत विश्वविद्यालय ही 'ए' ग्रेड प्राप्त कर सके हैं, वहीं 2,780 महाविद्यालयों के मूल्यांकन में मात्र 9 प्रतिशत महाविद्यालय ही 'ए' ग्रेड प्राप्त कर सके हैं। शिक्षण संस्थाओं में आधारभूत सुविधाओं की भी कमी है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त योग्य शिक्षकों की कमी भी गंभीर समस्या है। शिक्षकों की कमी का सीधा प्रभाव शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ता है। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के लिए शिक्षक एवं छात्र अनुपात एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बिन्दु है। इसी तरह उच्च शिक्षा में प्रवेश दर वर्ष 2014-15 में मात्र 23.6 प्रतिशत थी, जिसे 2020-21 तक 30 प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शिक्षकों के लगभग 50 प्रतिशत पद रिक्त हैं। शिक्षकों की कमी पूरी करने के लिए प्रयास किये जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि योग्य शिक्षकों की संख्या पूरी न होने पर छात्रों से अपेक्षा करना अनुचित है।

राज्यपाल ने कहा कि नवीन एवं क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप शोध कार्य होने चाहिए। शोध एवं नवोन्मेष में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्चकोटि की श्रेणी में वही शिक्षण संस्थायें हैं, जिनके यहाँ नवोन्मेष पर विशेष बल दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध उनकी प्राथमिकताओं में प्रदर्शित नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि सभी विश्वविद्यालयों में शोध एवं नवोन्मेष पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

श्री नाईक ने कहा कि देश में 759 विश्वविद्यालय हैं, जिसमें 350 राज्य विश्वविद्यालय हैं, 123 मानद विश्वविद्यालय हैं, 47 केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं तथा 239 निजी विश्वविद्यालय हैं। यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो राज्य में 27 राज्य विश्वविद्यालय/संस्थायें, 5 केन्द्रीय विश्वविद्यालय, 10 मानद विश्वविद्यालय तथा 24 निजी विश्वविद्यालय हैं। विभिन्न उद्योग घरानों द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काफी रूचि दिखाई गयी है, जिसके परिणामस्वरूप 6 नये निजी विश्वविद्यालय की स्थापना भी अभी हाल में हुई है। उन्होंने कहा कि शिक्षा एक मिशन है उसे व्यापार नहीं बनाया जाना चाहिए।

राज्यपाल ने कहा कि उच्च शिक्षा में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। राष्ट्र स्तर की उच्च शिक्षा की प्रवेश दर में क्षेत्रीय एवं छात्रों के सापेक्ष छात्राओं की प्रवेश दर में काफी अंतर है। उच्च शिक्षा तक सभी की पहुँच के लिए आवश्यक है कि क्षेत्रीय एवं लैंगिक असमानता को दूर किया जाये। गत वर्ष 22 विश्वविद्यालयों के दीक्षान्त समारोह में यह अनुभव किया गया कि छात्राओं ने 65 प्रतिशत पदक प्राप्त किये हैं। उन्होंने कहा कि इस स्थिति को देखते हुए महिलाओं को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से पिछड़े एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक शिक्षण संस्थान स्थापित किये जायें।

श्री नाईक ने कहा कि शिक्षा के लिए शासकीय बजट बढ़ना चाहिए। छात्रसंघ के चुनाव होने चाहिए ताकि नयी पीढ़ी में नेतृत्व का निर्माण हो। आज के तकनीकी युग में हमें अपने पुराने शिक्षा माध्यमों में बदलाव लाना होगा तथा उपलब्ध सूचना तकनीकों का अधिक से अधिक पठन-पाठन में प्रयोग करना चाहिए। ई-गवर्नेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए तथा व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास की आवश्यकता पर बल दिया जाना चाहिए। छात्रों में नौकरी पाने वाले के बदले, नौकरी देने वाले की मानसिकता का निर्माण करें। उन्होंने शैक्षिक संस्थाओं की सम्बद्धता, नियुक्तियों तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं के लिए कहा कि उसे पारदर्शी और सबके लिए समान होना चाहिए।

फोरम में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो० जी०सी० त्रिपाठी, पं० दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो० अशोक कुमार ने भी अपने विचार रखे। धन्यवाद ज्ञापन दैनिक जागरण के सम्पादक श्री दिलीप अवस्थी ने दिया।

-----

अंजुम/ललित/राजभवन (359/51)



